

मुख्य समाचार

- केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरें रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 लोकसभा में किया प्रस्तुत—कहा—विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना—देना नहीं।
- पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर का आरोप— कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल को लेकर जनता में फैला रही भ्रम।
- उप—मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा—केन्द्र ने प्रसाद योजना के तहत माता चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूर।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत चंबा व लाहौल—स्पिति के लिए चार करोड़ से पंचायत संसाधन केन्द्र स्वीकृत।

वक्फ विधेयक

संयुक्त संसदीय समिति द्वारा स्वीकृत किए गए वक्फ विधेयक, 2025 को आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरें रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना—देना नहीं है और यह केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून किसी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। किरें रिजिजू ने कानून को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि यह पूर्वव्यापी नहीं है और इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है।

किरें रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर—मुस्लिमों व अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार—विमर्श के बाद यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि गैर—मुस्लिमों को वक्फ में शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, यह सिर्फ अल्पसंख्यकों में डर फैलाने की राजनीति है।

अनुराग सिंह ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में प्रस्तुत वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल अन्याय की जड़ प्रहार है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को महिला व गरीब मुस्लिम समुदाय का विरोधी बताते हुए कहा कि भारत को वक्फ के खौफ से आजादी दिलाने का अब समय आ गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल को लेकर जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर वोट बैंक के लिए संविधान से समझौता करने का भी आरोप लगाया।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक वास्तव में वक्फ के लाभ का विधेयक है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि आज संसद में पेश किए गए इस विधेयक से देश की वक्फ संपत्तियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

इस बीच सांसद सुरेश कश्यप ने वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि संशोधन का उद्देश्य उम्मीद सुधार वक्फ संपत्तियों का सतत विकास और वक्फ संस्थानों का सशक्तिकरण करना है।

उप-मुख्यमंत्री

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया है कि केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत माता चिन्तपूर्णी मंदिर के लिए 56 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। वे आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन करने के अवसर पर बोल रहे थे। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने माता ज्वाली जी और श्री नैना देवी मंदिरों के लिए सौ-सौ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते दो दिनों में हरोली क्षेत्र के लिए करीब सवा सौ करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि इनमें 75 करोड़ रुपये की बीत क्षेत्र सिंचाई योजना चरण दो और 37 करोड़ रुपये की झलेड़ा घालूवाल फोरलेन पुल शामिल हैं।

राजीव भारद्वाज

केंद्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पिति जिलों के लिए दो-दो करोड़ रुपये की लागत से जिला पंचायत संसाधन केंद्र स्वीकृत किए हैं। आज लोकसभा में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन जिला पंचायत संसाधन केंद्रों के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायतों संस्थानों से जुड़े हितधारक समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

हर्षवर्धन चौहान

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिला के शिलाई में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले सौ बिस्तरों के नागरिक अस्पताल भवन का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए सौ बिस्तरों की व्यवस्था होगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर दूरदराज क्षेत्रों के अस्पतालों में ढांचागत व स्टॉफ सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिलाई क्षेत्र के लिए 68 करोड़ की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी गई है जिसमें से 28 करोड़ सिवरेज के लिए और 30 करोड़ से पानी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए गंभीर है और इस दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वे आज शिमला जिला के जुब्बल, नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में करीब करोड़ों रूपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले चामशु पुल से तीन पंचायतों रावी, भोलाड़ और मांदल के अलावा पब्वर नदी के समीप रह रहे किसानों को भी लाभ होगा। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे भविष्य में भी जारी रखने को कहा।

अधिसूचना

प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन की अधिसूचना आज जारी कर दी है। शिक्षा निदेशालयों को स्कूल शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय के रूप में पुनर्गठित किया गया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अब स्कूल शिक्षा निदेशालय के रूप में कार्य करेगा। यह निदेशालय बाल वाटिका से जमा दो कक्षा तक से संबंधित मामलों जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को देखेगा।

उत्सव

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में तीन दिवसीय तकनीकी महोत्सव 'मेराकी 2025' आज शुरू हुआ। इस महोत्सव में देशभर के विभिन्न आईआईटी, ट्रिपल आई टी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के 8 सौ से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। इस दौरान, छात्र हैकथॉन, परियोजना प्रदर्शनी, रोबोटिक प्रतियोगिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता चुनौतियां, साइबर सुरक्षा प्रतियोगिताओं और उद्योग-निर्देशित परामर्श सत्र जैसी विभिन्न तकनीकी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।